

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 83/2017

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1-श्रीमती शांतिदेवी पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी रामसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल असाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1-ग्राम पंचायत बांदरा जरिये सरपंच 2-जोराराम उर्फ जोर सिंह पुत्र नवलाराम 3-भीयाराम पुत्र नवलाराम 4-तोगा पुत्र नवलाराम के का०मुकाम- 4.1-बालाराम पुत्र स्व०तोगाराम सभी जातियान जाट निवासीगण भूरटिया तहसील व जिला बाडमेर
2-श्रीमती हऊवा पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल कालूडी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर
3-श्रीमती रेखा पुत्री स्व० कुष्टा पत्नी विरधा उर्फ विरधसिंह जाति पुरोहित निवासी पुरोहितो की बस्ती (बांदरा) बाडमेर हाल हडेतर तहसील सांचौर जिला जालोर		

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2016 मे राजस्व अपील संख्या 13/2012 अनवान शांतिदेवी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत बांदरा वगैरा मे दिनांक 26-5-2016 को पारित किया गया ।

उपस्थिति बहस:-

- 1- श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 2 से 4 की ओर से ।
- 3- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28-5-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बांदरा तहसील बाडमेर के खसरा नंबरान 384 रकबा 55.01 बीघा, खसरा नंबर 389 रकबा 71.13 बीघा तथा खसरा नंबर 390 रकबा 116.06 बीघा कुल रकबा 243 बीघा भूमि का खातेदार कुष्टा वल्द अजीता कौम पुरोहित सा० देह था । उक्त खातेदार के फोट होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 134 मृतक की पत्नी वीरो तथा उसकी तीन पुत्रियां वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया गया । उपरोक्त भूमि मे से खसरा नंबर 384 की कुल 55.01 बीघा भूमि का विरासत का नामांतरकरण दर्ज करने बाबत कोई कार्यवाही किये बिना ही उक्त भूमि का बेचान मृतक खातेदार कुष्टा की पत्नी वीरो द्वारा किया जाना बताते हुए म्युटेशन संख्या 6 बिना मृतक कुष्टा के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा दिनांक 15-7-62 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 6 के विरुद्ध अपीलाटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 के द्वारा खारीज कर दिया जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 384 की 55.01 बीघा भूमि मृतक खातेदार कुष्टा के नाम चल रही थी उक्त खातेदार कुष्टा के देहांत के बाद तत्कालीन पटवारी हल्का ने विरासत का नामांतरकरण दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की तथा रेस्पोंड के पूर्व पुरुष वगताराम पुत्र नवलाराम से मिलीभगत कर विधिविरुद्ध म्युटेशन संख्या 6 बेचान के आधार पर स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक के विधिक वारिसान जीवित थे परंतु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त म्युटेशन संख्या 6 विधिविरुद्ध स्वीकृत कर दिया जिसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प बांदरा मे ले जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 के द्वारा अस्वीकार करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि लोक अदालत मे पत्रावली को रखे जाने का अपीलांटगण का कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था तथा न ही प्रकरण पक्षकारान के बीच राजीनामे या सहमति का था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित कोर्ट मे चल रहे प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 के केम्प मे रखते हुए निर्णित करने मे विधिक भूल की है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार कुष्टा फोट हो गया था तथा कुष्टा द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया था । पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार कुष्टा के फोट होने पर उसके कायम मुकाम के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसे मे विरासत का नामांतरकरण दर्ज किये बिना तथाकथित बेचान का म्युटेशन संख्या 6 स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता था इस कारण म्युटेशन की कार्यवाही विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पंजीबद्ध बेचान पत्र से अंतरित होना तथा उसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के कारण का उल्लेख करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तथाकथित बेचाननामा अपीलांटगण द्वारा निष्पादित किया हुआ नहीं है ऐसे मे अपीलांटगण के हिस्से तक की भूमि का म्युटेशन स्वीकृत किया ही नहीं जा सकता था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच किये बिना स्वीकृत नामांतरकरण को चलेज करने पर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा दिया गया विवेचन विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है ।

अंत में वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 6 को निरस्त करने तथा विवादित भूमि का म्युटेशन मृतक कुष्टा के सभी वारिसान के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार कुष्टा ने ही खसरा नंबर 384 की 55.01 बीघा भूमि का बेचान रेस्पो0 संख्या 2 के पूर्व पुरुष वगताराम पुत्र नवलाराम कौम जाट को करने पर उक्त बेचाननामे के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 6 स्वीकृत किया था जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 के द्वारा अपीलांटगण की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1962 में बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था तब से अपीलाधीन भूमि रेस्पो0 के खाते में एवं कब्जे में चली आ रही है ऐसे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार 12 वर्ष से अधिक समय तक किसी भूमि पर कब्जा काश्त होने पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ऐसे में अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि में अपना हक अधिकार होना मानते हैं तो उन्हें विधिवत राजस्व वाद पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते हैं म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारों की घोषणा संभव नहीं है इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 6 एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 6 के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन खसरा नंबर 384 की 55.01 बीघा भूमि के खातेदार कुष्टा पुत्र अजीता कौम पुरोहित था तथा उक्त भूमि का बेचान उसकी पत्नी वीरो द्वारा रेस्पो0 के पूर्व पुरुष वगताराम पुत्र नवलाराम कौम जाट के पक्ष में करने पर बेचान दस्तावेज के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बांदरा द्वारा म्युटेशन संख्या 6 दिनांक 15-7-62 को स्वीकृत किया गया था, जिसमें प्रथमदृष्टियां कोई विधिक त्रुटि नहीं होना पाया जाता है ।

उक्त म्युटेशन संख्या 6 के विरुद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व खातेदार कुष्टा फोट हो गया था तथा कुष्टा द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया था । पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार कुष्टा के फोट होने पर उसके कायम मुकाम के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई ऐसे में विरासत का नामांतरकरण दर्ज किये बिना तथाकथित बेचान का म्युटेशन संख्या 6 स्वीकृत ही नहीं किया जा सकता था इस कारण म्युटेशन की कार्यवाही विधिविरुद्ध होने से निरस्त योग्य थी ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बेचान के दस्तावेज की वैधता एवं उसकी जांच करने तथा किसी प्रकार का अभिमत देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए रेस्पोंड संख्या 2 के पूर्व पुरुष वगताराम पुत्र नवलाराम के पक्ष में किये गये बेचान को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक उक्त बेचान के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में देते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अपीलांटगण यदि अपीलाधीन मूमि में अपना हक अधिकार होना मानती है तो नियमित वाद सक्षम न्यायालय में पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी होगी, म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-5-2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर